

प्रदेश में आईटी सेक्टर में 7 हजार करोड़ रुपए के नविश प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

3 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में आईटी सेक्टर में सात हजार करोड़ रुपए के नविश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार आईटी सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट में 2186 करोड़ रुपए का, एमएक्यू में 483 करोड़ रुपए और पीटीएम में 638 करोड़ रुपए का नविश नोएडा में करेगी तथा इस नविश के जरिये 14185 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- इसके अलावा, प्रदेश में डाटा सेंटर के लिये भी दो नविश प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें एक सगिपुर की कंपनी एसटीपी नोएडा में डाटा सेंटर के लिये 1130 करोड़ रुपए का नविश करेगी, जबकि एक अन्य कंपनी एसकेबीआर 2692 करोड़ रुपए का नविश करेगी। इन दोनों परियोजनाओं के जरिये 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
- कैबिनेट ने डाटा सेंटर नीति में बदलाव करते हुए हाल ही में ग्रेटर नोएडा में खुले उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर के बाद सूबे में 7 और डाटा सेंटर खोलने का फैसला किया है। इन सभी डाटा सेंटर के लिये भूमा अनुदान की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके अलावा ड्यूल फीडर की सप्लाई में एक फीडर की सप्लाई का खर्च वहन भी किया जाएगा।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स) अरवि कुमार ने बताया कि डाटा सेंटर के लक्ष्य को बढ़ाकर 900 मेगावाट के डाटा सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिये एफएआर की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है, ताकि निवेश जल्दी पास हो सके। इसमें पार्श्वित कंप्लीशन की व्यवस्था दी गई है, जबकि बिजली कनेक्शन को लेकर भी सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं।
- इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डाटा सेंटर की फीलड में भी दस करोड़ रुपए तक की फंडिंग की जाएगी। डाटा सेंटर में हुए इन बदलावों से न सिर्फ नविश बढ़ेगा, बल्कि यह और तेजी से भी आएगा। ये पॉलिसी 5 साल तक के लिये मान्य होगी।
- अरवि कुमार ने बताया कि प्रदेश में तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले ही खोले जा चुके हैं तथा 5 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और खोले जाएंगे, जिनमें ये सेंटर 3डी प्रिंटिंग, 5जी, वर्चुअल रिएलिटी, स्पेसटेक जैसे नये क्षेत्र में खुलेंगे। स्कूल स्तर पर ही इनोवेटिव कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सस्टेनेबल अलाउंस को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 17.5 हजार रुपए किया गया है।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रोटोटाइप बनाने के लिये भी अब 5 लाख रुपए का अनुदान मिल सकेगा। ग्रामीण परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले, कूड़े को रसाइकल करने वाले, पर्यावरण संरक्षण, रनियूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में स्टार्ट-अप शुरू करने वालों को 50 प्रतिशत अधिक इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी वाले स्टार्ट-अप को भी परिभाषा तय की गई है, जिसके तहत स्टार्ट-अप में 26 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होना जरूरी है।
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विश्वविद्यालयों को मंजूरी भी दी है, जिनमें कर्नाटक का विख्यात जेएसएस विश्वविद्यालय नोएडा में, एसडी सहि विश्वविद्यालय फतेहगढ़-फर्रुखाबाद में और एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय गाज़ियाबाद में खोला जाएगा। इन तीनों विश्वविद्यालयों को आशय-पत्र जारी कर दिये गए हैं।